

दैनिक

न्याय साक्षी

अधिकार से न्याय तक

आवश्यक सूचना

आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्याससाक्षी अधिकार से न्याय तक का सर्व का कार्य तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्व की टीम आपके घर विजित करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

RNI NO - CHHIN/2018/76480 || Postal Registration No-055/Raigarh DN CG || रायगढ़, रविवार 29 अगस्त 2021 || पृष्ठ-4, मूल्य 3 रूपए || वर्ष-03, अंक- 329

महत्वपूर्ण एवं खास



अब सुल्तानपुर जिले का नाम 'कुश भवनपुर' रखने की तैयारी में योगी सरकार

लखनऊ (आरएनएस)। उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जिले का नाम बदलकर अयोध्या करने के बाद अब इसके पड़ोसी जिले सुल्तानपुर का नाम भी जल्द भगवान राम के बेटे कुश के नाम पर 'कुश भवनपुर' रखा जा सकता है. सूत्रों का कहना है कि नाम बदलाने का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ रेवेन्यू द्वारा राज्य सरकार को भेज दिया गया है. इसकी मंजूरी के लिए अगली कैबिनेट में फैसला लिया जाएगा. जिला गजेटियर में ऐतिहासिक रिकॉर्ड का हवाला देते हुए सुल्तानपुर जिला प्रशासन की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि शहर को साल 1300 में कुश भवनपुर के रूप में जाना जाता था. अलाउद्दीन खिलजी की सेना द्वारा आक्रमण किए जाने से पहले भर वंश यहां पर शासन करता था. खिलजी के आक्रमण के बाद इसका नाम बदलकर सुल्तानपुर कर दिया गया था. एक रिपोर्ट के मुताबिक सुल्तानपुर जिला मजिस्ट्रेट रवीश गुप्ता ने कहा कि कुछ महीने पहले जब हमने जिला गजेटियर के आधार पर रिकॉर्ड देखा तो पता चला कि लगभग साल 1300 में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान शहर को उसकी सेना ने तबाह कर दिया था. तब से इसे सुल्तानपुर के नाम से जाना जाता है. कुछ महीने पहले ही हमने सरकार को इसकी जानकारी दी थी. 21 दिसंबर 2018 को लंभुआ से बीजेपी विधायक देवमणि द्विवेदी ने सुल्तानपुर का मुद्दा उठाया था. उन्होंने दावा किया था कि उन्हें कुछ ऐतिहासिक रिकॉर्ड मिले हैं, जो दिखाते हैं शहर को कुश से जुड़े विभिन्न नामों से जाना जाता था और सदन को सर्वसम्मति से कुश भवनपुर के नाम को मंजूरी देनी चाहिए.

असम में बाढ़ से स्थिति बिगड़ी, करीब 1.33 लाख लोग प्रभावित गुवाहाटी (आरएनएस)। असम के 11 जिलों में शुक्रवार को बाढ़ की स्थिति बिगड़ने से 39,000 से अधिक बच्चों सहित 1.33 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं और 7,584 हेक्टेयर से अधिक फसल क्षेत्र जलमग्न हो गये हैं। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एसडीएमए) के अधिकारी के अनुसार, सबसे बुरी तरह प्रभावित पांच जिले बोगाईनाम (63,891 लोग प्रभावित), धेमाजी (31,500), माजुली (13,239), डिब्रूगढ़ (10,697) और चिरांग (10,634) हैं। एसडीएमए के अनुसार, 243 गांव प्रभावित हुए और बाढ़ प्रभावितों की मदद के लिए 74 राहत शिविर खोले गए हैं। एसडीएमए बुलेटिन में कहा गया है कि कई जिलों में बाढ़ के पानी से कई सड़कें, पुल, तटबंध, पुलिया और अन्य बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा है।

दो मंजिला इमारत की छत गिरी, मलबे में फंसी एक बच्ची

रेस्क्यू ऑपरेशन जारी पुणे (आरएनएस)। पुणे से सटे पिंपरी चिंचवड शहर के पुणेवाडी इलाके में शनिवार सुबह एक दो मंजिला इमारत की छत गिर गई. जानकारी के अनुसार इमारत जर्जर हालत में थी. दुर्घटना के बाद मलबे में एक महिला अपनी दो बेटियों के साथ फंस गई. कुछ देर प्रयास के बाद एक बेटे और मां बाहर निकलने में कामयाब. लेकिन अभी भी एक 15 साल की बच्ची मलबे में फंसी हुई है. जानकारी के अनुसार मौके पर दमकल की दो टीमों रेस्क्यू के काम में जुटी हुई है. वहीं छत का बचा हुआ हिस्सा धीरे-धीरे गिर रहा है. इसलिए रेस्क्यू ऑपरेशन में परेशानी आ रही है.

देश में कोरोना की तीसरी लहर के संकेत

पिछले 24 घंटे में 46,759 नए मरीज, 509 की मौत

नई दिल्ली (आरएनएस)। देश में कोरोना संक्रमण के मामले एक बार फिर से बढ़ने से तीसरी लहर के संकेत सामने आने लगे हैं। पिछले 24 घंटे में 46,759 नए कोरोना मरीज मिले हैं, जबकि 509 लोगों की मौत हुई। हालांकि 31,374 मरीजों को ठीक होने पर अस्पताल से छुट्टी भी दी गई है।

कोविड-19 मृत्यु दर 1.34 प्रतिशत है। इस दौरान 31,374 मरीज ठीक होने के बाद देश में अब तक 3,18,52,802 लोग संक्रमण मुक्त होकर कोरोना को मात दे चुके हैं। वहीं उपचाराधीन मरीजों की संख्या में लगातार चौथे दिन बढ़ोतरी हुई और पिछले 24 घंटे में उपचाराधीन मरीजों की संख्या में 14,876 मामले बढ़े। इस प्रकार देश में उपचाराधीन मरीजों की संख्या बढ़कर 3,59,775 हो गई है, जो कुल मामलों का 1.10 प्रतिशत है। मरीजों के ठीक होने की राष्ट्रीय दर है, जिनमें से महाराष्ट्र के 1,36,900 लोग, कर्नाटक के 37,248 लोग, तमिलनाडु के 34,835 लोग, दिल्ली के 25,080 लोग, उत्तर प्रदेश के 22,796 लोग, केरल के 20,313 लोग और पश्चिम बंगाल के 18,410 लोग थे। इसके अलावा देश में कोरोना संक्रमण के मामले एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं। बीते 24 घंटे में 46,759 नए पॉजिटिव मरीज मिले हैं। केरल में एक दिन में 32, 809 नए मामले सामने आए हैं। जबकि



महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की संख्या में थोड़ी राहत आई है। यहां पिछले 24 घंटे में 4600 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। **इक्वायन करोड़ से ज्यादा की जांच-** मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार देश में अभी तक कुल 51,68,87,602 नमूनों की कोविड-19 संबंधी जांच की गई है, जिनमें से 17,61,110 नमूनों की जांच शुक्रवार को की गई। दैनिक संक्रमण दर 2.66 प्रतिशत है, जो पिछले 33

दिन से तीन प्रतिशत से कम है। वहीं साप्ताहिक संक्रमण दर 2.19 प्रतिशत है, जो पिछले 64 दिन से तीन प्रतिशत से कम है। **देश में 62.29 करोड़ का टीकाकरण-** मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार भारत में शुक्रवार को कोविड-19 टीके की रिकॉर्ड 1,03,35,290 खुराक लगाई और देश में कोविड-19 रोधी टीकों की कुल 62.29 करोड़ खुराक दी जा चुकी हैं। लोगों को ये खुराक 67,19,042 सत्रों में दी गई है। **टीकाकरण में भारत ने रचा इतिहास-** शुक्रवार को देशभर में 1 करोड़ से ज्यादा कोरोना वैक्सीन की खुराक लगाई गई है, जो किसी एक दिन में टीकाकरण का अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इसी के साथ भारत में अब तक 62 करोड़ से ज्यादा लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई गई है। देशभर में सबसे ज्यादा वैक्सीन उत्तर प्रदेश में लगाई गई है।

यहां 28 लाख 62 हजार 649 लोगों को कोरोना टीका लगाया गया। वहीं, दूसरे नंबर पर कर्नाटक रहा, यहां 10 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई गई, जबकि महाराष्ट्र में 984117 लोगों को वैक्सीन की डोज दी गई। इसी तरह हरियाणा में 6 लाख लोगों का टीकाकरण हुआ। **इस प्रकार बढ़ा संक्रमण का ग्राफ-** देश में पिछले साल सात अगस्त को संक्रमितों की संख्या 20 लाख, 23 अगस्त को 30 लाख और पांच सितम्बर को 40 लाख से अधिक हो गई थी। वहीं संक्रमण के कुल मामले 16 सितम्बर को 50 लाख, 28 सितम्बर को 60 लाख, 11 अक्टूबर को 70 लाख, 29 अक्टूबर को 80 लाख और 20 नवम्बर को 90 लाख के पार चले गए। देश में 19 दिसम्बर को ये मामले एक करोड़ के पार, चार मई को दो करोड़ के पार और 23 जून को तीन करोड़ के पार चले गए थे।

पीएम जन-धन योजना वित्तीय समावेशन का राष्ट्रीय मिशन ने सात वर्ष पूरे किए

नई दिल्ली (आरएनएस)। वित्त मंत्रालय हाशिए पर रहने वाले और अब तक सामाजिक-आर्थिक रूप से उपेक्षित वर्गों का वित्तीय समावेशन करने और उन्हें सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। समावेशी विकास का प्रवर्तक होने के नाते वित्तीय समावेशन इस सरकार की राष्ट्रीय प्राथमिकता है। यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह कदम गरीबों को उनकी बचत को औपचारिक वित्तीय प्रणाली में लाने का एक रास्ता प्रदान करता है और उन्हें गांवों में अपने परिवारों को पैसे भेजने के अलावा सूदखोर साहूकारों के चंगुल से बाहर निकालने का एक अवसर प्रदान करता है। प्रधानमंत्री जन-धन योजना (पीएमजेडीवाई) इस प्रतिबद्धता

की दिशा में एक अहम पहल है। यह वित्तीय समावेशन से जुड़ी दुनिया की सबसे बड़ी पहलों में से एक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2014 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दिए गए अपने संबोधन में प्रधानमंत्री जन-धन योजना (पीएमजेडीवाई) की घोषणा की थी। 28 अगस्त को इस योजना की शुरुआत करते हुए, प्रधानमंत्री ने इस अवसर को गरीबों की एक दुष्कर से मुक्ति के उत्सव के रूप में निरूपित किया था। प्रधानमंत्री जन-धन योजना (पीएमजेडीवाई) की सातवीं वर्षगांठ के मौके पर, वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने इस योजना के महत्व को दोहराया।

सेना के पूर्व अधिकारी सहित दो लोगों ने रक्षा कर्मियों को लगाया 29 करोड़ रुपये का चूना, मिली पांच साल कैद की सजा

नई दिल्ली (आरएनएस)। ओडिशा प्रोटेक्शन ऑफ इंटररेस्ट्स ऑफ डिपॉजिटर्स एक्ट से निपटने वाली एक अदालत ने रक्षा कर्मियों को ठगने के आरोप में एक सेवानिवृत्त सेना के अधिकारी सहित दो लोगों को पांच साल की कैद की सजा सुनाई है. अदालत ने शुक्रवार को सैनिक कल्याण संगठन के प्रमुख लेफ्टिनेंट कर्नल (सेवानिवृत्त) राकेश राणा और ब्रुकसन इन्फ्रा प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर पूर्ण चंद्र पांडा को पांच

साल की कैद की सजा सुनाई है. जानकारी के मुताबिक, दोनों पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. राकेश राणा और पूर्ण चंद्र पांडा ने कई रक्षा कर्मियों से रियासत भूमि देने का वादा करके उनसे लगभग 29 करोड़ रुपये की राशि ठगी है. हालांकि, दोनों जमीन नहीं दे सके और बार-बार अपील के बावजूद रक्षा कर्मियों को पैसे वापस नहीं किए. ठगे गए रक्षा कर्मियों ने राणा और पांडा के खिलाफ ओडिशा पुलिस की आर्थिक अपराध

शाखा में शिकायत दर्ज कराई थी. पुलिस ने मामलों की जांच करते हुए राणा और पांडा के खिलाफ आईपीसी की विभिन्न धाराओं और ओपीआईडी एक्ट की धारा 6 के तहत मामला दर्ज किया था. मामले में सुनवाई करते हुए ओपीआईडी कोर्ट ने दोनों को और कंपनी को उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों का दोषी पाते हुए सजा सुनाई है. ओपीआईडी (विशेष) अदालत के विशेष लोक अभियोजक विस्वजीत महापात्रा ने कहा, 'कारावास के

अलावा राणा और पांडा को एक एक लाख रुपये जुर्माना भरने का निर्देश दिया गया है. इसी तरह कंपनी पर भी दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. मालूम हो कि इससे पहले, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (सीबीआई) ने सर्विस सिलेक्शन बोर्ड (एसएसबी) के जरिए सैन्य अधिकारियों के चयन में भ्रष्टाचार करने के आरोप में लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक के 6 अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज किया था.

रूस से 70 हजार एके-103 राइफल खरीदेगा भारत

भारतीय वायुसेना की बढ़ती ताकत

नई दिल्ली, 28 अगस्त (आरएनएस)। भारतीय वायुसेना ने आपातकालीन खरीदारी के तहत रूस से 70 हजार एके-103 राइफल खरीदने का करार किया है। यह सेना में मौजूद इंसाम राइफलों की जगह लेंगी। ऐसे समय में जब भारत में सक्रिय आतंकवादी समूहों को अफगानिस्तान में अमेरिकी सैनिकों द्वारा छोड़े गए हथियार मिलने की संभावना है, यह डील वायुसेना की ताकत में बढ़ोतरी करने के लिए अहम है। एके-103 राइफलों भारत को अगले कुछ महीनों में ही उपलब्ध हो जाएगी। इससे देश की सेना को आतंकियों से निपटने में मदद मिलेगी।



सरकार के सूत्र के अनुसार सेना को इस वक्त करीब 1.5 लाख नई अर्सेल राइफल की दरकार है। इसी को ध्यान में रखते हुए रूस से 70,000 एके-103 अर्सेल राइफल खरीदने के लिए आपातकालीन प्रवधानों के तहत पिछले सप्ताह लगभग 300 करोड़ रुपये के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए थे। हथियार सबसे पहले जम्मू-कश्मीर,

श्रीनगर जैसे संवेदनशील हवाई बेसों के साथ फील्ड एरिया में सैनिकों को मुहैया कराए जाएंगे। बाकी बची राइफलों की पूर्ति भारत और रूस के बीच होने वाली ज्यादा उन्नत एके-203 राइफल की डील के जरिए की जाएगी। एके-203 अर्सेल राइफलों के अनुबंध सेना के तहत किया जा रहा है। सेना को अपने सैनिकों की मारक क्षमता को मजबूत करने के लिए करीब 6.5 लाख राइफलों की जरूरत है। वहीं, वायुसेना की जरूरत को पूरा करने के लिए 4,000 एसआईसी अर्सेल राइफलों को खरीदने की तैयारी की जा रही है। सीधे रूस से खरीदने की तैयारी दरअसल, भारत ने 2019 में रूस

के साथ उत्तर प्रदेश में ऑर्डनेंस फैक्टरी बोर्ड के कोखा प्लांट में 7.5 लाख एके-203 राइफल बनाने का करार किया था, लेकिन प्लांट में अब काम शुरू नहीं हो पाया। यही वजह है भारत ने 70 हजार राइफल सीधे रूस से खरीदने का फैसला किया है। इससे पहले लाइन ऑफ एक्जुअल कंट्रोल पर चीन से चल रहे विवाद के दौरान भारत ने अमेरिका से भी 1.44 लाख एसआईसी सॉर राइफल इमरजेंसी प्रक्योरमेंट के तहत सीधे खरीदी थीं। हालांकि, एसआईसी सॉर राइफल भारतीय सेना के लिए खरीदी गई थी और इनका इस्तेमाल भारतीय सेना ने शुरू कर दिया है। एलओसी और एलएसी, दोनों ही मोर्चों पर तैनात भारतीय सैनिक इन राइफल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं।

आयुष चिकित्सा प्रणाली ने लोगों की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई: कोविन्द

राष्ट्रपति ने गोरखपुर में महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी

गोरखपुर (आरएनएस)। राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने कहा कि कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में विशेष रूप से महामारी के प्रकोप की दृष्टी लहर में, आयुष चिकित्सा प्रणाली ने लोगों की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने यह बात आज 28 अगस्त, 2021 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष



विश्वविद्यालय की आधारशिला रखने के अवसर पर कही। राष्ट्रपति द्वारा नींव रखे जाने के बाद वहां बारिश हुई। राष्ट्रपति ने इसे परियोजना के लिए शुभ संकेत बताया।

सभा को संबोधित करते हुए, राष्ट्रपति ने कहा कि हमारे देश में प्राचीन काल से स्वास्थ्य और उपचार की कई पारंपरिक और गैर-पारंपरिक प्रणालियां प्रचलित हैं। भारत सरकार ने इनके

विकास के लिए निरंतर प्रयास किए हैं। चिकित्सा की इन प्रणालियों की व्यवस्थित शिक्षा और अनुसंधान के लिए, 2014 में आयुष मंत्रालय का गठन किया गया था। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 2017 में आयुष विभाग की भी स्थापना की थी। उन्होंने विश्वास जताया कि महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय की स्थापना के साथ, प्रदेश के आयुष चिकित्सा संस्थान इस विश्वविद्यालय से संबद्ध होकर अपने-अपने क्षेत्र में बेहतर कार्य कर सकेंगे। राष्ट्रपति ने कहा कि ऐसा माना जाता है कि बाबा गोरखनाथ उन अग्रदूतों में से एक रहे हैं जिन्होंने आपातकालीन दवाओं के रूप में खनिजों और

धातुओं से दवाएं तैयार की हैं। इसलिए इस विश्वविद्यालय का नाम महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय रखना बेहद उपयुक्त है। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत अनेकता में एकता का सर्वोत्तम उदाहरण है। भारत के लोग जनहित में जो भी हितकर है, उसे स्वीकार करने में संकोच नहीं करते। हमारे देश में विभिन्न प्रकार की चिकित्सा पद्धतियों का प्रचलन भी इसी सोच का परिणाम है। योग, आयुर्वेद और सिद्धा विश्व के लिए भारत का योगदान है। राष्ट्रपति ने कहा कि आज संपूर्ण विश्व में चिकित्सा की एकीकृत प्रणाली के विचार को मान्यता दी जा रही है। विभिन्न चिकित्सा प्रणालियां लोगों को

एक दूसरे की पूरक प्रणाली के रूप में ठीक करने में मदद कर रही हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि यद्यपि आदिवासी समुदाय में जड़ी-बूटियों और जड़ी-बूटियों के ज्ञान की समृद्ध परंपरा रही है, लेकिन पिछले दो दशकों में लोकप्रियता पूरे देश में बढ़ी है। औषधीय जड़ी-बूटियों और पौधों की बढ़ती मांग के परिणामस्वरूप किसानों और वनवासियों की आय में वृद्धि के साथ-साथ रोजगार के मौके पैदा हो रहे हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि गोरखपुर में महायोगी गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय की स्थापना से आयुष प्रणालियों की शिक्षा और लोकप्रियता को और बढ़ावा मिलेगा।